उत्तर कोरिया का वैश्विक आर्थिक प्रतिबन्ध के विरुद्ध आर्थिक रणनीति का विश्लेषण

अमित सिंह

सारांश

उत्तर कोरिया पर पिछले तीन पीढियों से एक ही वंश का निरंकुश शासन आज के लोकतान्त्रिक युग में एक महत्वपूर्ण परिघटना है । लम्बे समय तक कोरिया जापान का उपनिवेश रहा था । जिसने इसे 1950 – 53 कोरिया युद्ध के बाद स्वतंत्र औद्योगिक नीति निर्माण में सहायता प्रदान किया उस समय सोवियत संघ ने उत्तर कोरिया को व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध बनाया । किन्तु सोवियत संघ के विघटन ने इसकी अर्थव्यवस्था को भारी संकट में डाल दिया । साथ ही, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया। उत्तर कोरिया की परमाणु नीति ने भी इसकी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाया इन सब समस्या के बावजूद उत्तर कोरिया के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है । प्रस्तुत शोध इस बात का पता लगाना है इतने प्रतिबंधो के बावजूद उत्तर कोरिया इतनी बड़ी सेना का संचालन के लिए धन कहा से प्राप्त करता है । पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया की कुछ केंद्रीय समिति जैसे ब्यूरो 39 के कार्यो के अध्ययन में पाया गया कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के लिए अवैध हथियारों, ड्रग्स तस्करी , नकली नोट , क्रिप्टोकरन्सी और वन्य जीवो से जुड़े अवैध व्यापार का सहारा लिया है, उत्तर कोरिया की साइबर गतिविधियाँ न केवल अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए , बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की पूरी अखंडता के लिए सीधा खतरा हैं। (Bartlett,2020) यह अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है । इसकी जड़े अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद (हिजबुल्लाह, हमास) से भी जुड़ी हुई है ।

प्रमुख शब्दावली : लोकतान्त्रिक युग, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, ब्यूरो 39, , क्रिप्टोकरन्सी, हिजबुल्लाह, हमास ।

परिचय

उत्तर कोरिया 1950 के दशक से ही औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध रहा है । सोवियत संघ की सहायता से उत्तर कोरिया ने चीन और दक्षिण कोरिया से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है । यही कारण है कि 1960 के दशक में उत्तर कोरिया में प्रति व्यक्ति आय, दक्षिण कोरिया की तुलना में सर्वाधिक थी । 1970 के दशक में उत्तर कोरिया ने सोवियत संघ को लोकोमोटिव , चीन को सिंथेटिक्स , यूरोप को मशीन टूल्स , अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को कृषि मशीनरी और रासायनिक उर्वरक निर्यात किया । देश का अधिकांश उद्योग हमहंग-हंगहम औद्योगिक परिसर के आसपास केंद्रित था । उत्तर कोरिया मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज था । 1946 में इसने स्वयं को औद्योगिक समाज के रूप में स्थापित किया । जिसमे राष्ट्रीय उत्पाद का 70 प्रतिशत हिस्सा खनन, विनिर्माण और सेवाओं से प्राप्त होता है ; लगभग 30 प्रतिशत अभी भी कृषि से आता है। हालाँकि, बंद और कठोर आर्थिक प्रणाली ने विकास बाधित किया और पूर्वी यूरोपीय साम्यवाद के पतन के बाद व्यापारिक साझेदारों के नुकसान से अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई । दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक सेना को समर्पित संसाधनों की मात्रा भी अर्थव्यवस्था पर बोझ रही है । शीत युद्ध के अंत ने उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल कर रख दिया । शीत युद्ध के अंत के बाद, उत्तर कोरिया गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है । 1991 में सोवियत संघ के पतन ने उत्तर कोरिया को अपने मुख्य सहयोगी और समर्थक से वंचित कर दिया , जिसके परिणामस्वरूप विदेशी

* अथिति व्याख्याता , शास.वि.या.ता.स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़

सहायता में भारी कमी आई । इस नुकसान के साथ-साथ 1990 के मध्य में बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने एक विनाशकारी अकाल को जन्म दिया , जो 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2000 के प्रारंभ तक चला । 2002 में सरकार ने सीमित आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की , जिसमें बाजारों को कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करने और निजी व्यापारियों को अनुमति देना शामिल था अनुमान है कि इस काल में सैकड़ों हजारों उत्तर कोरियाई लोगों की मृत्यु हुई । इस समय, उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था, जो मुख्यतः राज्य-नियंत्रित थी , संकट के लक्षण दिखाने लगी। 1990 के दशक के मध्य में जीडीपी में भारी गिरावट आई, और कृषि क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुआ। खाद्य की कमी को दूर करने के लिए , सरकार ने अपनी पकड़ ढीली करना शुरू किया, जिससे अनौपचारिक बाजार का उदय हुआ। 1990 के दशक के अंत तक , लोगों ने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैकल्पिक साधनों की खोज की, जिसके कारण बाजार गतिविधियां बढ़ने लगीं।

किम जोंग-इल के तहत 'सैनिक पहले' नीति (सॉंगुन)

किम जोंग-इल, जिन्होंने 1994 में किम इल-सुंग के निधन के बाद नेतृत्व संभाला , ने 1990 के दशक के अंत में "सैनिक पहले" नीति (सॉंगुन) को लागू किया। इस रणनीति का उद्देश्य सैन्य शक्ति को सुनिश्चित करना और रक्षा खर्च को आर्थिक विकास पर प्राथमिकता देना था। अर्थात देश के सम्पूर्ण संसाधन पर सैन्य का अधिकार था इसे अन्य क्षेत्रो की तुलना ज्यादा अधिकार और प्राथमिकता दी गई । इस नीति के परिणामस्वरूप संसाधनों का गलत आवंटन हुआ , जिससे आर्थिक संकट और बढ़ गया। 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में सीमित आर्थिक सुधार भी देखे गए। 2002 में, किम जोंग-इल ने " 7.1 उपाय" की घोषणा की , जिसका उद्देश्य आर्थिक नियंत्रण को विकेंद्रीकरण करना और कुछ बाजार तंत्रों को प्रोत्साहित करना था। इन उपायों के तहत किसानों को बाजारों में अधिशेष उत्पाद बेचने की अनुमति दी गई , लेकिन यह राज्य के नियंत्रण में था। हालाँकि , इन सुधारों के मिश्रित परिणाम थे और अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

2009 की मुद्रा सुधार

2009 में, उत्तर कोरिया ने महंगाई को कम करने और अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए एक मुद्रा सुधार लागू किया। सरकार ने अपनी मुद्रा का पुनर्गठन किया , पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा के लिए विनिमय करने की सीमा तय की। इस कदम से व्यापक असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि इससे कई बाजार प्रतिभागियों की बचत समाप्त हो गई। इस सुधार के परिणाम भयानक थे ; महंगाई बढ़ी और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान होता रहा, क्योंकि लोगों ने सरकार की नीतियों पर विश्वास खो दिया।

किम जोंग-उन का उदय और ब्योन्गजिन नीति

किम जोंग-उन की सत्ता में आने के बाद 2011 में उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था के लिए एक और परिवर्तनशील समय शुरू हुआ। प्रारंभ में, उसकी सरकार ने "ब्योन्गजिन" नीति अपनाई , जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों की क्षमताओं के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समानांतर विकास को बढ़ावा देना था। यह दृष्टिकोण विकास की कोशिशों को स्थगित किए बिना आर्थिक स्थिति को सुधारने का लक्ष्य रखता था। किम जोंग-उन के तहत , उत्तर कोरिया में आर्थिक गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई , विशेष रूप से विदेशी व्यापार और निवेश में। हालांकि सरकार ने अर्थव्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण कायम रखा , लेकिन बाजार-उन्मुख सुधारों की दिशा में एक स्पष्ट धक्का था। इसका एक उदाहरण विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाए गए थे , अक्सर चीनी भागीदारों के साथ। किम जोंग-उन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर भी एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया , अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की। 2018 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ शिखर सम्मेलन और

उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई मुलाकात , आर्थिक रियायतों के लिए परमाणु निरस्त्रीकरण के कदम उठाने के उद्देश्य से किए गए थे।

वर्तमान चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

हालांकि ये प्रयास जारी हैं, लेकिन उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बाधित है , जो इसके निरंतर परमाणु हथियार कार्यक्रम के कारण हैं। COVID-19 महामारी ने पहले से ही नाजुक आर्थिक स्थिति को और बढ़ा दिया , सीमाएँ बंद हो गईं और व्यापार सीमित हो गया , जो आयात और निर्यात के लिए आवश्यक था। आर्थिक परिदृश्य अब भी गंभीर है , जिसमें कमी, सीमित विदेशी मुद्रा, और अनौपचारिक बाजारों पर निर्भरता शामिल है। इस प्रकार, शीत युद्ध के बाद उत्तर कोरियाई अर्थव्यवस्था का इतिहास कठिनाइयों, अनुकूलन, और सुधार के प्रयासों से भरा है। सैन्य प्राथमिकताओं और आर्थिक जरूरतों के बीच का यह अंतर्विरोध उस स्थिति को बनाए रखता है , जहां सरकार राज्य द्वारा संचालित परियोजनाओं के माध्यम से वैधता और स्थिरता की तलाश करने के साथ-साथ एक अधिक बाजार-उन्मुख जनसंख्या की वास्तविकताओं का सामना कर रही है। जैसे-जैसे किम जोंग-उन का शासन आगे बढ़ता है , मौलिक प्रश्न यह रहेगा कि क्या उत्तर कोरिया अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं के साथ आर्थिक अस्तित्व और विकास की आवश्यकताओं को सुलझा सकेगा। उत्तर शीघ्र ही क्षेत्र और वैश्विक समुदाय के साथ उसके संबंधों की दिशा को निर्धारित कर सकता है।

वैश्विक आर्थिक प्रतिबंध

उत्तर कोरिया के खिलाफ वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों का इतिहास उसके परमाणु महत्वाकांक्षाओं , भू-राजनीतिक तनावों और मानवाधिकारों के उल्लंघन को दर्शाता है। (Frank, 2006) यहाँ पर उत्तर कोरिया पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण प्रतिबंधों का एक सारांश दिया गया है:

1. **प्रारंभिक उपाय (1950 के दशक-1990 के दशक)**:

- कोरिया युद्ध (1950-1953) के बाद, संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया के आक्रमण के जवाब में शुरुआती प्रतिबंध लगाए। हालांकि, ये प्रतिबंध लागू करने में प्रभावी नहीं रहे क्योंकि उस समय कोरिया प्रायद्वीप पर भू-राजनीतिक ध्यान कम था।

2. **परमाणु विकास पर ध्यान (1993-2006)**:

- उत्तर कोरिया के परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से हटने के बाद 1993 में, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास और प्रतिबंधों को बढ़ाना शुरू किया।
- 2006 में, उत्तर कोरिया के पहले परमाणु परीक्षण के बाद, UNSC ने संकल्प 1718 अपनाया, जिसमें संपत्ति की फ्रीज और सैन्य निर्यात तथा लग्ज़री सामानों पर प्रतिबंध शामिल थे।

3. **बढ़ते प्रतिबंध (2009-2016)**:

- 2009 में उत्तर कोरिया के दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद, UNSC ने संकल्प 1874 अपनाया, जिसने हथियार निर्यात पर कड़े प्रतिबंध और कुछ लग्ज़री सामानों के निर्यात पर रोक लगाई।

- उत्तर कोरिया के निरंतर परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप, 2016 तक UNSC ने अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जो कोयला, लोहे, समुद्री भोजन और अन्य प्रमुख निर्यात पर आधारित थे।

4. **व्यापक प्रतिबंध (2017-वर्तमान)**:

- 2017 में उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों और छठे परमाणु परीक्षण के जवाब में, UNSC ने कुछ सबसे कड़े प्रतिबंधों को अपनाया, विशेष रूप से संकल्प 2371 और 2375, जो उत्तर कोरिया के वार्षिक निर्यात राजस्व के एक तिहाई को समाप्त करने का लक्ष्य रखते थे।

- इन प्रतिबंधों में कोयला, वस्त्र और समुद्री भोजन जैसे महत्वपूर्ण निर्यात को लक्षित किया गया और इसे सीमित करने के लिए परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की पहुंच सीमित की गई।

5. **अमेरिका के प्रतिबंध**:

- UN प्रतिबंधों के अलावा, अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अपने स्वयं के प्रतिबंध लगाए, विशेष रूप से उत्तर कोरिया प्रतिबंध और नीति सुधार अधिनियम (NKSPEA) के तहत, जो मानवाधिकारों के उल्लंघन, साइबर हमलों और आतंकवाद के समर्थन पर केंद्रित हैं।

- अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया के प्रमुख व्यापार भागीदार, को अधिक सख्ती से प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रभावित करने का काम किया है, विशेषकर अवैध व्यापार प्रथाओं के खिलाफ।

6. **प्रतिबंधों का प्रभाव**:

- ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल चुके हैं, जिससे खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है, और चीन पर अधिक आर्थिक निर्भरता बढ़ी है।

- इसके बावजूद, उत्तर कोरिया ने अवैध व्यापार गतिविधियों के माध्यम से, प्रतिबंधों को चकमा देने की क्षमता दिखाई है।

उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों के इतिहास में, ध्यान हमेशा उसकी परमाणु क्षमताओं को नियंत्रित करने पर केंद्रित रहा है, जबकि मानवता के मुद्दों और प्रतिबंधों के उत्तर कोरियाई लोगों पर प्रभाव के जटिल राजनीतिक परिदृश्य का सामना किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच उत्तर कोरिया की आर्थिक रणनीति

उत्तर कोरिया ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई रणनीतियों अपनाई हैं। ये रणनीतियाँ किम जोंग-il और किम जोंग-un दोनों के नेतृत्व में विकसित हुई हैं।

1. **आर्थिक नीति सुधार**: किम जोंग-un के तहत, एक अधिक बाजार-उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीति सुधार हुए हैं। 'जिम्मेदार खेत प्रणाली' और 'स्व-समर्थन लेखांकन प्रणाली' जैसी पहलों को उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक

प्रबंधन में स्वायत्तता बढ़ाने के लिए पेश किया गया है, जिससे राज्य-नियंत्रित मॉडल से एक अधिक बाजार-उन्मुख दृष्टिकोण में संक्रमण हुआ है,।

2. **सैन्य और आर्थिक समांतर नीति पर जोर**: किम जोंग-un की दोहरी रणनीति (ब्युघजिन) में परमाणु क्षमताओं और अर्थव्यवस्था के विकास को समानांतर रूप से प्राथमिकता दी गई है। यह नीति यह बताती है कि रक्षा को मजबूत करना आर्थिक निर्माण के साथ सह-अस्तित्व में हो सकता है, जिससे शासन को संसाधनों को प्रभावी ढंग से आवंटित करने और सैन्य निवेश को न्यायसंगत ठहराने की अनुमति मिलती है।

3. **बाजार विस्तार और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था**: शासन ने धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों पर अपनी पकड़ ढीली की है, जिससे अनौपचारिक बाजारों का फलना-फूलना संभव हुआ है। अनुमान है कि कुल अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा काफी बढ़ गया है, जिससे नागरिकों को व्यापार और छोटे स्तर के उद्यम करने की अनुमति मिलती है, भले ही प्रतिबंधों के कारण आधिकारिक राज्य संसाधनों पर चोट पहुंची हो।

4. **विदेशी निवेश और व्यापार क्षेत्र**: उत्तर कोरिया ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए हैं, और चीन के साथ व्यापार के महत्व पर जोर दिया है। ये क्षेत्र निवेश को सुविधा प्रदान करने और विदेशी मुद्रा उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो पारंपरिक व्यापार मार्गों पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं,।

5. **अनुकूलन और लचीलापन**: उत्तर कोरिया ने आर्थिक रणनीतियों को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करने में दक्षता हासिल की है, जिसमें बदलते प्रतिबंध और आंतरिक आवश्यकताएं शामिल हैं। देश में अर्थशास्त्र में अनुसंधान इन अनुकूलनों को न्यायसंगत ठहराने और लागू करने पर केंद्रित है, जो राज्य-नायक आर्थिक पहलों और सुधारों का समर्थन करता है।

कुल मिलाकर, सुधार-उन्मुख नीतियों, बाजार की अनुकूलता और समग्र विकास पर रणनीतिक जोर के माध्यम से, उत्तर कोरिया प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक जीवनशीलता की कोशिश करता है।

किम जोंग-इल के तहत आर्थिक रणनीति

किम जोंग-इल की आर्थिक दृष्टिकोण ठंडी युद्ध के बाद हुए गंभीर आर्थिक संकटों से प्रभावित थी। "सेना पहले" नीति (सोंगुन) को 1998 में औपचारिक रूप से अपनाया गया और यह आर्थिक आवश्यकता के मुकाबले सैन्य वित्तपोषण को प्राथमिकता देती थी , जिसे आर्थिक संकट के बीच शासन को स्थिर रखने के लिए तैयार किया गया था। इस रणनीति का परिणाम अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय गिरावट था, जिसमें 1993 से 1996 के बीच जीडीपी में भारी कमी आई और 90 के दशक के मध्य में औपचारिक खाद्य राशन समाप्त हो गए। हालांकि बाजार अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ , जो 1990 में लगभग 7% से 2000 तक 10% के करीब पहुंच गया , लेकिन यह वृद्धि अधिकांशतः शासन के खाद्य अधिग्रहण और बाजार गतिविधियों पर नियंत्रण को ढीला करने के परिणामस्वरूप हुई , न कि सरकार की सक्रिय नीतियों के माध्यम से।

किम जोंग-उन के तहत आर्थिक रणनीति

2011 में किम जोंग-उन के नेतृत्व में परिवर्तन के साथ , अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सुधार-केंद्रित प्रबंधन की ओर एक स्पष्ट बदलाव देखा गया , जबकि जूच के सिद्धांतों को बनाए रखा गया। अपनी प्रशासन की शुरुआत में , किम जोंग-उन ने विभिन्न सुधारों की शुरुआत की जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाना था , जिसमें "ज़िम्मेदार कृषि प्रणाली" और मूल्य निर्धारण तथा राजस्व वितरण के प्रणालियों में बदलाव शामिल थे। आर्थिक पहलों के लिए मंत्रिमंडल के नियंत्रण को बढ़ाने के साथ-साथ उद्यमों में आर्थिक स्वायत्तता बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किए गए। मार्च 2013 में , किम जोंग-उन ने "ब्युंगजिन" नीति का पेश किया , जिससे उनका उद्देश्य परमाणु क्षमताओं और आर्थिक विकास को एक साथ बढ़ावा देना था , जो उनकी रक्षा और आर्थिक प्राथमिकताओं के बीच संतुलन को दर्शाता है। इससे 2016 –2020 के राष्ट्रीय आर्थिक विकास की पांच वर्षीय रणनीति जैसी पहलों की शुरुआत हुई , जिसने मैक्रोइकोनॉमिक प्रबंधन और आर्थिक इकाइयों की स्वायत्तता को बढ़ाने पर जोर दिया। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईडीजेड) का विकास विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया , जिसमें चीन जैसे देशों के अनुभवों से सीखने के प्रयास शामिल थे।इस प्रकार, उत्तर कोरिया की आर्थिक रणनीतियों को राज्य नियंत्रण , धीरे-धीरे बाजार उदारीकरण और सैन्य शक्ति के साथ-साथ आर्थिक सुधार की दोहरी खोज से वर्गीकृत किया गया है , जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और आंतरिक संसाधनों की सीमाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करते हुए किया गया है। (Pinkston, 2020)

उत्तर कोरिया के मुख्य आर्थिक साझेदार मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया हैं , जिसमें चीन सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यह साझेदारी ऐतिहासिक और भू-राजनीतिक संदर्भों के कारण महत्वपूर्ण है , खासकर शीत युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की आर्थिक कठिनाइयों के समय । कुल मिलाकर, जबकि चीन उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है , शासन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को नेविगेट करने और प्रतिबंधों के प्रभावों को कम करने के लिए अपने आर्थिक साझेदारों को विविधता लाने की कोशिश कर रहा है।

अवैध व्यापार

उत्तर कोरिया विभिन्न प्रकार के अवैध व्यापार में संलग्न है , जिसमें ड्रग्स और हथियारों की तस्करी शामिल है। ये गतिविधियाँ अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने और अपनी अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए की जा रही हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया गया है:

1. **ड्रग्स की तस्करी** : उत्तर कोरिया ने अवैध ड्रग्स , विशेषकर मेथाम्फेटामाइन और अफीम , का उत्पादन और निर्यात किया है। रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि शासन ड्रग तस्करी का उपयोग अपने कार्यों को वित्त देने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए करता है। कुछ आरोप हैं कि उत्तर कोरियाई अधिकारी ड्रग उत्पादन और वितरण नेटवर्कों का प्रबंधन कर रहे हैं, जो चीन और अन्य देशों में फैलते हैं।

2. **हथियारों का प्रसार** : उत्तर कोरिया का हथियारों की तस्करी का लंबा इतिहास है , जो विभिन्न देशों और गैर-राज्य अभिनेताओं को हथियार प्रदान करता है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों , पारंपरिक हथियारों और सैन्य तकनीक का अवैध निर्यात शामिल है। शासन अक्सर अपनी सैन्य क्षमताओं का उपयोग करके विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है , जो उसकी संप्रभुता को बनाए रखने और उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

3. **प्रतिबंधों से बचाव**: ड्रग्स और हथियारों की अवैध व्यापार अक्सर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने के लिए व्यापक प्रयासों के साथ जुड़ी रहती है। उत्तर कोरिया ने सामानों की तस्करी के लिए जटिल नेटवर्क विकसित किए हैं , जो जहाजों और गुप्त तरीकों का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा पहचान से बचते हैं। प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित किया है, जिससे शासन को अपनी अवैध गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया ।

4. **अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रतिक्रिया**: वैश्विक समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगी देशों ने उत्तर कोरिया के अवैध व्यापार गतिविधियों को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया है , जिनमें प्रतिबंध और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कूटनीतिक प्रयास शामिल हैं। हालांकि , ये पहलों विभिन्न स्तरों पर सफल विश्लेषण करने में असफल रही हैं, और उत्तर कोरिया अपने अवैध व्यापार में लिप्त रहना जारी रखता है ।

इन गतिविधियों को दबाने के प्रयासों के बावजूद , उत्तर कोरिया का अवैध व्यापार में संलग्न होना अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है। (Jin, 2011)

अमेरिका की कूटनीति

अमेरिका की उत्तर कोरिया नीति कई वर्षों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरी है, विशेष रूप से उत्तर कोरिया के परमाणु महत्वाकांक्षाओं और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य से प्रभावित होकर। यहां अमेरिकी नीति के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

1. परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान: अमेरिका की नीति का प्रमुख केंद्र परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य रहा है। यह लक्ष्य ओबामा प्रशासन की "स्ट्रैटेजिक पेटियंस" (कूटनीतिक धैर्य) दृष्टिकोण के दौरान सख्त किया गया , जिसका उद्देश्य कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डालकर उत्तर कोरिया को अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए प्रेरित करना था।

2. प्रतिबंध और दबाव: आर्थिक प्रतिबंध अमेरिकी नीति में एक मुख्य उपकरण रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों के वित्तपोषण को रोकने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। यह दृष्टिकोण 2016-2017 के दौरान उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षणों और मिसाइल लॉन्च के बाद तेजी से बढ़ा।

3. कूटनीतिक संवाद: अमेरिका ने भी कूटनीतिक संवाद के प्रयास किए, विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन के दौरान, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और किम जोंग-उन के बीच अभूतपूर्व शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया गया। इन बैठकों का उद्देश्य सीधे संवाद स्थापित करना और संकट के समाधान के लिए कूटनीतिक रास्ता खोजना था, हालांकि ये संसद में ठोस समझौतों में नहीं बदले।

4. सैन्य तत्परता: अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में एक सैन्य उपस्थिति बनाए रखी है और संभावित उत्तरी कोरियाई आक्रामकता के खिलाफ रोकथाम के संकेत के रूप में संयुक्त अभ्यास करता है। यह सैन्य तत्परता उत्तर कोरिया के खतरों को नियंत्रित करने के लिए व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

5. क्षेत्रीय गठबंधन: अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करता है ताकि उत्तर कोरिया के आक्रामकता के खिलाफ एक एकजुट मोर्चा तैयार किया जा सके। इन सहयोगियों के बीच नीति का समन्वय उत्तर कोरियाई खतरे का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

6. मानवाधिकार मुद्दे: सुरक्षा और निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, उत्तर कोरिया में मानवाधिकार मुद्दे भी अमेरिका की नीति चर्चा का हिस्सा रहे हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मानवतावादी सहायता प्रदान की है, हालाँकि इस प्रकार की सहायता अक्सर राजनीतिक संदर्भ द्वारा जटिल हो जाती है।

ये तत्व उत्तर कोरिया के प्रति एक जटिल और गतिशील दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो दबाव, संवाद और क्षेत्रीय भागीदारों के साथ सहयोग का मिश्रण है। उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमताओं से संबंधित चल रही चुनौतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण नीति दुविधाएँ पेश करती हैं।

निष्कर्ष

उत्तर कोरिया ने वैश्विक आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ अपनी आर्थिक रणनीति को अद्वितीय तरीके से विकसित किया है। 2018 में, देश ने संप्रभुता और आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए कई आवश्यक उपाय किए। आंतरिक आर्थिक समस्याओं जैसे मुद्रा अवमूल्यन, महंगाई, और आयात की कमी ने उसे संकटकाल में रिसर्च और सुधार के लिए प्रेरित किया। किम जोंग- un की नवीनतम पार्टी लाइन में 'सोशलिस्ट आर्थिक निर्माण' की बात की गई, जो दर्शाता है कि सरकार आत्मनिर्भरता और स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। 2018 में चीन के साथ व्यापार में तेज गिरावट, विशेष रूप से निर्यात में 85% की कमी, ने उत्तर कोरिया को वैकल्पिक व्यापार और निवेश के तरीकों की तलाश करने पर मजबूर किया। (Kriebitz, 2020) इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने निजीकरण के कुछ प्रयास शुरू किए, जैसे कि राज्य के संपत्तियों का बिक्री या पट्टा देना, और श्रम की लागत को बढ़ाने की बात की। हालांकि, इन सुधारों के साथ-साथ चुनौती भी है। यदि सरकार ने वैकल्पिक मार्गों को नहीं अपनाया, तो महंगाई और बेरोजगारी सामाजिक संकट में तेजी ला सकती है। विशेष रूप से, चीन और अन्य देशों से सहायता की उम्मीदों के सहारे रहकर, उत्तर कोरिया के लिए आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन बहुत कठिन साबित हो सकता है। संक्षेप में, उत्तर कोरिया की आर्थिक रणनीति वैश्विक प्रतिबंधों के समय में स्वयं को बचाने एवं सुधार के लिए साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाती है। अर्थव्यवस्था के समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय और व्यावहारिक कदम उठाए जाने की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक प्रतिरोध और आंतरिक संघर्ष इस प्रक्रिया में प्रमुख बाधा बन सकते हैं।

Reference

- Bartlett, J. (2020). *Exposing the Financial Footprints of North Korea's Hackers*. Center for a New American Security. http://www.jstor.org/stable/resrep27457

- Frank, R. (2006). THE POLITICAL ECONOMY OF SANCTIONS AGAINST NORTH KOREA. *Asian Perspective*, *30*(3), 5–36. http://www.jstor.org/stable/42704552

- Jin, K. K. (2011). THE DEFECTOR'S TALE: Inside North Korea's Secret Economy. *World Affairs*, *174*(3), 35–46. http://www.jstor.org/stable/41290342

- Kriebitz, A. (2020). North Korea's Knowledge Economy and Foreign Direct Investment. *North Korean Review*, *16*(2), 7–25. https://www.jstor.org/stable/26975891

- Pinkston, D. A. (2020). North Korea's Objectives and Activities in Cyberspace. *Asia Policy*, *15*(2), 76–83. https://www.jstor.org/stable/27023903